(In Nos.)

Private Sector :	
5. M/s. CIMM Co. Ltd.	3,580
6. M/s. Hindustan General Industries	2,000
7. M/s. Modern Industries	2,000
8. M/s. Texmaco Ltd.	4,800
9. M/s. Hindustan Development Corpn.	4,056

उपभोक्ता वस्तुओं का अंधाधुंध आयात

1576. **श्री सुंदर सिंह भंडारी:** क्या **प्रधान मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता वस्तुओं के अनुचित और अंधाधुंध आयात को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) सरकार इस उद्देश्य के लिए वर्तमान कानूनों में किन-किन संशोधनों पर विचार कर रही है ; और

(ग) उपभोक्ता वस्तुओं के अनुचित आयात को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये गये है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) वर्तमान आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुओं को प्रतिबंधित आयात सूची के तहत रखा गया है और इसी कारण इनका आयात नहीं किया जा सकता है जो विशेष आयात लाइसेंस होने अथवा इस संबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के मामले में लागू नहीं हैं।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की तस्कर विरोधी एजेंसियों को उपभोक्ता वस्तुओं के अवैध आयात को रोकने एवं पकड़ने के लिए सजग किया जाता है । तस्करी रोकने तथा पता लगाने में संबंधित सभी एजेंसियों के बीच गहन तालमेल रखा जा रहा है । तस्करी की वस्तुओं को जब्त करने और दोषियों को दंडित करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन कार्यवाही की जाती है । बड़ी तस्करी के मामलों में अपराधियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधि निवारण, अधिनियम, 1974 के तहत गिरफ्तार किया जाता है ।

BHEL's capacity to bid the power projects

1577. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

SHRI NILOTPAL BASU:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether as per the Power Ministry, the possibility of Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL) for bidding for power projects is linked with its capacity to back the standard commercial practice like supplier's credit;

(b) if so, what action has been taken by Government to enable BHEL to raise finance to provide commercial supplier's credit; and

(c) whether any effort has been made by Government to form a consortium between BHEL and NTPC for making a concerted effort in building power plants within India against global bidding?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (c) The possibility of BHEL's success in its future bids will be crucially influenced by its ability to arrange suppliers' credit. BHEL has initiated steps to set up a Financial Services Company towards that end. BHEL & NTPC have come together in a joint bid and their enlarged cooperation will follow perceived commonalty of commercial interests.

Revival of sick companies registered with BIFR

1578. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the cumulative losses of 1,294 sick companies registered with the BIFR amounted to Rs. 19,945 crore, as reported in a news item published in the Hindustan Times dated 28th February, 1995 under the heading 'Economy and Business';

(b) if so, what are the details thereof, State-wise, Sector wise, delay-wise case in submission of reports by operating agencies thereby hampering work of BIFR in exploration of alternative measures for revival of sick companies during 1993-94 and till date;

(c) whether BIFR has issued any guidelines or asked the operating agencies to look for management changes, ordered sale of sick industrial companies or sanctioned merger thereof in order to revive sick industrial companies, if so, the latest position till date; and

(d) whether the RBI and BIFR have held discussions jointly in this regard, or issued fresh guidelines with a view to expedite revival of sick units in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा लोहे के कतरन (स्क्रैप) के आयात में धोखाधड़ी

1579. **श्री जगेश्वर मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में विदेशों से आयातित लोहे की कतरन (स्क्रैप) के स्थान पर वास्तव में, ट्रकों में रेत भरी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्तियों या संस्थाओं का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) दिनांक 25 जनवरी, 1995 को मैसर्स मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन के माध्यम से आयातित लोहे की कतरन (कतरनों के टुकड़े) के भरे छह ट्रक तीन प्राधिकृत परिवाहकों के माध्यम से सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट (सी.एफ.एफ.पी.) हरिद्वार में पहुंचे । ट्रकों की सामग्री की द्वार पर जांच की गई और यह पाया गया कि सामग्री का 50% से अधिक भाग कतरन के बजाय लोहे के के चूरे के रूप में था ।

जांच और पूछताछ के परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया है कि केवल अच्छी किस्म की सामग्री को हिसाब में लिया जाए और परिवाहकों से हानियों की वसूली की जाये । सी.एफ.एफ.पी. हरिद्वार में उन परिवाहकों के साथ और कारोबार पर रोक लगा दी है ।